Indian Council of World Affairs
Sapru House, Barakhamba Road
New Delhi

4था सप्रु हाउस व्याख्यान

द्वारा

महामहिम श्री अब्दुल्ला शाहिद

पुपील्स मजलिस के अध्यक्ष

मालदीव गणतंत्र

विषय

"मालदीव में लोकतंत्र संबंधी चुनौतियां"

स्थान

सप्रु हाउस, नई दिल्ली

7 मई, 2013

महामहिम, देवियों और सज्जनों

भारत की यात्रा करना और विशेषकर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की राजधानी नई दिल्ली जैसे जिंदादिल और सुंदर शहर में आना सदा ही सौभाग्य की बात है।

मैं बड़ा सत्कृत हूं और माननीय लोक सभा अध्यक्ष मीरा कुमार के इस आमंत्रण के प्रति बहुत ही कृतज्ञ हूं ; यहां आने के बाद मेरे शिष्टमंडल और मुझे मिले इस स्वागत और भव्य आतिथ्य सत्कार से बहुत ही अभिभूत हूं।

यह पहला अवसर नहीं कि है कि मुझे आधिकारिक और अन्यथा भी दिल्ली में आने का अवसर प्राप्त हुआ।किंतु इस समय पहली बार मैं मालदीव के संसद पुपील्स मजलिस के अध्यक्ष के रूप में एक द्विपक्षीय सरकारी दौरे पर भारत की यात्रा पर हूं और इसलिए इस दौरे का मेरे लिए विशेष महत्व है ; मैं आपके पास मालदीव के लोगों से एक विशेष संदेश लेकर आया हूं।

और मेरे मित्र यह संदेश भारत के प्रति सम्मान , मित्रता और प्रशंसा और अपार कृतज्ञता व दृढ़ता की सरहना के लिए है जिसके साथ भारत सदा ही अच्छे या बुरे दिनों में मालदीव और उनके नागरिकों के लिए एक अच्छे पड़ोसी के रूप में अपनी उदारता के साथ अविचल, अडिग और बिना समझौता खड़ा रहा है।

समय और फिर से, ऐसे कई लोग हैं जो हमारे दोनों देशों के आकार और शक्ति के स्पष्ट अंतर को इंगित करते हैं और यह बताते हैं कि इस तरह के अंतर से हमारे रिश्ते में एक असमानता फैलेगी जो किसीन किसी रूप में इस छोटे से देश के लिए नुकसानदेह होगा और कि हमारी संप्रभुता और स्वतंत्रता से समझौता होगा; हमसे अपेक्षा की जाएगी कि हम अपने बहुत बड़े और शक्तिशाली पड़ोसी के हितों को हमेशा स्वीकार करें

किंतु सच्चाई कुछ और ही है!

एक व्यक्ति जिन्हें भारत-मालदीव संबंधों का अनुभव है, जो दो दशकों से अधिक समय से इन दोनों देशों के बहुत निकट रहा है, के रूप में मैं यह प्रमाण के साथ कह सकता हूं कि जहां इन दोनों देशों के बीच भ्रातृत्व संबंध के असंख्य उदाहरण हैं वहीं हम भारत के साथ बातचीत के दौरान एक 'छोटे देश' का भाव कभी महसूस नहीं किया है। सचमुच भारत ने सदा ही मालदीव के साथ उनके आकार के निरपेक्ष समान साझेदार के रूप में कार्य किया है। अच्छे मित्र और निकट पड़ोसी के रूप में कई मुद्दों पर हमारे बीच अंतर और मतभेद रहे हैं किंतु इन मतभेदों ने कभी भी हमारे विश्वास को प्रभावित नहीं किया है अथवा आपसी संबंध

को हानि नहीं पहुंचा है, हमने सदा ही एक दूसरे की सहायता की है।

विदेश सेवा के अधिकारी के रूप मेंऔरबाद में एक राजनेता के रूप मेंमुझेकई मौकों परऔर कई स्तरों पर एवं कई बार तो सबसे ऊंचे स्तर पर भारत सरकार के साथ बातचीत करने का अवसर मिला। हर अवसर परभारत गोल मोल बात किए अथवा प्रतिदान के बिना सहायता देने में कभी भी पीछे नहीं रहा जैसा कि 2004 की सूनामी आपदा और 1988 के 3 नवंबर को मालदीव की संप्रभुता पर सशस्त्र हमले के दौरान दी गयी सहायता उल्लेखनीय है। बेशक , यही कुछ ऐसे मामले नहीं थे जब मालदीव ने भारतीय उदारता का अनुभव कियाबल्किऔर भी बहुत ऐसे अवसर रहे हैं। हमारे दोनों देशों के बीच कई दशकों से बने इस तरह के आशंकारहित सहयोग और अच्छे विश्वास ने हमारी दोस्ती को द्विपक्षीय स्तर पर मजबूत कियाऔर साथ ही बहुपक्षीय क्षेत्र मेंहमारे सहयोग के दायरे को व्यापक और गहरा किया।

देवियों और सज्जनों,

आज, मालदीव 'राजनीतिक सूनामी' का सामना कर रहा हैजो पिछले वर्ष फरवरी में सत्ता में अचानक बदलाव से उत्पन्न हुई अराजकता के संदर्भ में है। देश में राजनीतिक विमर्श तीव्र रूप से पक्षपातपूर्ण हो गया हैऔर राजनीतिक नेताओं के बीच आपसी अविश्वास की कमी आ गयी है। आगामी राष्ट्रपति चुनावों में भाग लेने के लिए कुछ उम्मीदवारों की पात्रता के बारे में प्रचलित अनिश्चितता से विरोधी राजनीतिक दलों के बीच प्रतिद्वंद्विता और बढ़ गई है। जैसा कि हम इस वर्ष के अंत में होने वाले 2008 के संविधान के तहत दूसरे राष्ट्रपति चुनावों की ओर बढ़ रहे हैं , हमें एक बार फिर अपने अंतरराष्ट्रीय मित्रों की बुद्धिमान परामर्शदाता , रचनात्मक अनुबंध और सहयोगपूर्ण सहायता की आवश्यकता होगीताकि मालदीव के लोगों और उनकी आशाओं व सपनों को फिर से जीवित किया जा सके जो लोकतांत्रिक परिवर्तन में निहित है।

जब मालदीव ने बहु दलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुना और वर्ष 2008 में अपना पहला स्वतंत्र और भय मुक्त चुनाव कराया तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारे मित्र इस मतदान के माध्यम से शक्ति के शांतिपूर्ण हस्तांतरण में हमारी खुशी में शामिल हुए। अनंत संघर्षों और असंख्य विघ्नों से भरी इस दुनिया में मालदीव का एकाधिकावार व्यवस्था से रक्तपात के बिना ही लोकतांत्रिक व्यवस्था में आना न केवल मालदीव के लोगों के लिए बल्कि अंतरराष्ट्रीय समुदायों , जो इसे अपनी सफलता की कहानी के रूप में मानते हैं, के लिए एक उत्कृष्ट विजय मानते हैं।

दुखद रूप से आज यह स्पष्ट है कि जिस सफलता को हमने 2008 में मनाया था , वास्तविक की अपेक्षा अधिक अवास्तविक था। गरिमापूर्ण समारोहों के तले सांस्कृतिक विरासत की गहरी आंतरिक समस्याएं , मौद्रिक और मानव दोनों संदर्भों में गंभीर संसाधन सीमाएं और साथ ही साथ विचारशील शासन की कला में अनुभवहीनता भी हैं। कुछ के लिए , ऐसा लगता था कि लोकतंत्र अराजकता और अव्यवस्था के अलावा कुछ नहीं था ; उनके लिएलोकतंत्र के तहत किए गए वायदे पूरे नहीं हुए ; ऐसे लोगों के लिए , जिन्हें अधिकार और आज्ञाकारिता की संस्कृति का पोषण किया गया था, लोकतंत्र एक क्रूर और 'असभ्य' प्रणाली बन गया था , जिसमेंसरकार और बुजुर्गों के प्रति कोई सम्मान नहीं था।एक उत्पादक विमर्श होने के बजायबहस और असंतोष मूल्यवान समय की बर्बादी के रूप में माना गया थाजिसमेंबुद्धिमत्तापूर्ण निर्णयों के माध्यम से समाज के निर्माण में योगदान देने के बजाय दक्षता से समझौता करना और देश के सामाजिक ताने बाने को नष्ट किया गया।

यह याद रखना उचित है कि 800 वर्षों से अधिक समय तक मालदीव पर सत्तावादी सुल्तानों द्वारा शासन किया गया हलांकि 1932 में एक लिखित संविधान को अपनाया गया।शासन की गणतांत्रिक व्यवस्था को अपनाए जाने के बाद 1968 में सुल्तान से एक 'निर्वाचित' राष्ट्रपति के रूप में सत्ता के हस्तांतरण ने किसी भी तरह से कार्यपालिका की शक्तियों में कमी नहीं की , जिसने राजनीतिक अर्थव्यवस्था और लोगों की सामाजिक भलाई के हर पहलू को नियंत्रित करना जारी रखा। वे न केवल मुख्य कार्यकारी थे , बल्कि न्याय के अंतिम मध्यस्थ और देश के कानूनों के प्रवर्तक भी थे। वास्तव में , राष्ट्रपति के विवेक को अक्सर संसद के माध्यम से पारित कानून की तुलना में कहीं अधिक बोलबाला होता है , एक ऐसी संस्था जिसे सदस्यों के माध्यम से राष्ट्रपति की पकड़ में मजबूती से रखा गया था, दोनों मनोनीत और निर्वाचित थे, जो कार्यपालिका की इच्छाओं के प्रति समर्पित रहे।

इस प्रकार वह जनसंख्या जो कई सदियों से अपने शासकों की निरंकुशता और दासता के टुकड़ों पर पली , उनके लिए शक्तियों के पृथक्करण का नया अंगीकृत सिद्धांत एक अनजान सिद्धांत था जिसे सहजता से पचाया नहीं जा सकता था। और न ही यह राजनीतिक दलों के 'सजातीय एकता' के खुराक पर पली जनसंख्या के अनुरूप विचारों में भिन्नता का स्पष्ट और लोक प्रदर्शन के साथ अचानक उभार था। उसी प्रकार, नव सृजित स्वतंत्र राज्य निकाय मंहगे तरीके से अपने अधिदेशों जिन्हें प्राय: अन्य राज्य संस्थाओं के साथ विवाद में खींच लाया करता था , की व्याख्या करते हुए अपने पृथक और भिन्न पहचानों को स्थापित करने के लिए बहुत अधिक उत्सुक थे।

देवियों और सज्जनों,

जहां यह दावा करना अपरिपक्वता होगी कि मालदीव में लोकतंत्र असफल हो गया है , वहीं यह भी स्पष्ट है कि राजनीतिक दलों की उपस्थिति में जल्दबाजी में अधिकारों के पृथक्करण को स्थापित करते हुए , अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करते हुए, स्वतंत्र राष्ट्रीय संस्थाओं की

स्थापना करते हुए और अंतरराष्ट्रीय रूप से सत्यापित किए जाने योग्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोजित करते हुए जल्दबाजी में बनाए गए संविधान से धारणीय लोकतंत्र नहीं आता है। राजनीतिक घटनाक्रमों जिसने नए राजनीतिक माहौल सृजित किया है , को देखते हुए और अगस्त , 2008 में नए संविधान को स्वीकार किए जाने के बाद से हम अब कई चूकों को महसूस करते हैं जिसमें देश में पहली बार लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार की असफलता में अंतर्निहित और कारकथे।

मैं यह दावे के साथ कहूंगा कि आगामी राष्ट्रपति चुनाव मालदीव में लोकतंत्र के भविष्य की एक महत्वपूर्ण चुनौती होगी। यह एक धारणीय और जीवंत लोकतांत्रिक भविष्य के लिए हमारे द्वारा उठाए गए प्रायोगिक कदमों की अभिपुष्टि करने में मदद कर सकता है अथवा इससे देश में ही दो फाड़ हो सकती है क्योंकि संभावित राष्ट्रपति के उम्मीदवारों के समर्थकों और आलोचकों के बीच शत्रुता की तीव्रता उत्तरोत्तर पक्षपात पूर्ण और पहले से अधिक भावनात्मक बन गया चुका है।

मालदीव निराशाजनक रूप से बहुत अधिक विभाजित रहा है जिस पर तत्काल मलहम लगाए जाने की आवश्यकता है। ऐसी उपचारात्मक प्रक्रिया को सितम्बर में मतदान प्रक्रिया के माध्यम से लोगों द्वारा दिए गए निर्णय के सार्वभौमिक सम्मान के प्रति गंभीर प्रण करने के लिए सभी राजनीतिक दलों को एक साथ आकर महसूस किया जा सकता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जिसमें लोगों द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों को बाधा रहित प्रतिस्पर्धा का मौका दिया गया , वह बेहतरीन है , यदि नहीं तो देश के लिए एकमात्र रास्ता बच जाता है कि वह लोकतांत्रित सामान्य स्थिति के रास्ते पर वापस चले और भविष्य की आस करे। राजनीतिक नेताओं को लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के सिद्धांतों का पालन के प्रति कटिबद्ध होना चाहिए जो स्वयं को चुनाव परिणाम में विजेताओं और पराजितों के रूप में देखने के स्थान पर व्यापक राष्ट्रीय हित वाला हो।

मैं अंतरराष्ट्रीय समुदाय से आग्रह करूंगा कि वे जब चुनाव हो रहे हैं तो इन चुनावों की तैयारी के दौरान मालदीव में अपनायी जा रही चुनावी प्रक्रिया में गंभीरता पूर्वक और सक्रिय रूप से शामिल हों और परिणाम का अनुसरण करें। हमें न केवल कुछ स्थानों का अवलोकन करने के लिए चुनाव के दिन बल्कि इस समग्र चुनावी प्रक्रिया से अवगत होने के लिए उनकी आवश्यक है।मुझे विश्वास है कि किसी चुनाव में केवल मतदान कार्य ही शामिल नहीं होता है बल्कि चुनाव के पूर्व , चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद समग्र चुनावी माहौल में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की आवश्यकता होती है। चूंकि मालदीव अपने लोकतांत्रिक

प्रत्यायकों को बहाल करने की कोशिश कर रहा है।

इसलिए नए चुने नेताओं में अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा विश्वास मत भी देश के भीतर और विदेश में नए नेताओं हेतु वैधता देने में एक अनिवार्य कारक होगा।

देवियों और सज्जनों,

आज अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं अनंत सद्भावना और हार्दिक मित्रता की भावना की परिपुष्टि करना चाहता हूं जो भारत के लोगों के लिए मालदीव के लोगों में असीमित रूप से उभर रहा है।

हम मालदीव वासियों के लिए भारत केवल पड़ोसी देश भर नहीं है। हमारे लिए भारत एक उभरती विश्व शक्ति है। हमारे लिए भारत हमारे लिए एक संसाधन मात्र नहीं है जिससे हम अपनी कई आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और न ही भारत वह ‘शक्तिशाली रक्षक’ है जिनके पास हम खतरे के समय जाते हैं। भारत हमारा मित्र है। और हमें विश्वास है कि हम सदा ही मित्र बने रहेंगे। आपका धन्यवाद!

***